



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154 ]  
No. 154 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1997/भाद्र 4, 1919  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1997/BHADRA 4, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

विदेशों में संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश हेतु दिशा निर्देश

फा. सं. 4/3/97-ई पी (ओ आई):— विदेशों में संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश हेतु दिनांक 7-11-96 और 26-3-97 की अधिसूचना सं. 4-1-93 ई पी (ओ आई) के साथ पठित दिनांक 17-8-95 की अधिसूचना सं. 4-1-93-ई पी (ओ आई) के द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं:—

- (1) पैरा 1.3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा; “उपर्युक्त को देखते हुए एक्जिम नीति के नीतिगत ढांचे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सभी आवश्यक स्वीकृतियों देगा और कथित वचनबद्धताएं निर्धारित करके प्रगति को मानीटर करेगा।”
- (2) पैरा 2.3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा: “ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होते।”
  - (1) भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश पर;
  - (2) बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश पर;
  - (3) प्राधिकृत वितरकों द्वारा स्वीकृत ई ई एफ सी अधिशेष से उपलब्ध कराई गई निधि के अधिकतम 15 मिलियन आरीकी डालर तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर; और
  - (4) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की अनुमति से प्राप्त की गई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट्स (जी डी आर) से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई 50% तक की अधिकतम राशि पर ऊपर की क्रम सं. I से IV के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर अलग-अलग कार्य विधियों के रूप में विचार किया जाएगा जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक/आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (3) पैरा 5.1 (III) में “निवेश की राशि” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:—
 

“ई ई एफ सी/जी डी आर कोष की वह निवल राशि जो कि ई ई एफ सी/जी डी आर फास्ट ट्रैक के अन्तर्गत निकासी के योग्य बन जाती” पैरा 5.1 (III) का शेष अंश वही रहेगा।

- (4) पैरा 5.2 (3) में "भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे।  
 "निवेश की समग्र सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष मूल्य का 50% गारन्टी के रूप में लिया जाना चाहिए"
- (5) पैरा 5.7 में, पैरा की तीसरी और चौथी पंक्ति में आए शब्द वित्तीय वर्षों/वित्तीय वर्ष के स्थान पर क्रमशः "कैलेंडर वर्षों/कैलेंडर वर्ष" रखा जाएगा।
- (6) पैरा 7.1 (ग) के बदले निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए।  
 "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के धटक के रूप में प्रस्तावित ई ई एफ सी/जी डी आर निधि सहित भारतीय पार्टी के संसाधनों, कुल पूंजी और कार्य कलापों के पैमाने के संदर्भ में पूंजी निवेश की प्रस्तावित राशि और विदेश स्थित उद्यम का आकार; 'और'
- (7) पैरा 7.1 (घ) में पैरा की पहली पंक्ति में "स्वदेश में योजना" के बाद निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :  
 "ई ई एफ सी/जी डी आर कोष की वह निवल राशि जी ई ई एफ सी/जी डी आर फास्ट ट्रैक के अन्तर्गत निकासी के योग्य हो जाती है" पैरा 7.1 (घ) का शेष अंश वही रहेगा।
- (8) पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा,  
 15.00 मिलियन अमरीकी डालर (नेपाल में भारतीय रुपया के निवेश पर लागू नहीं) से अधिक के पूंजी निवेश प्रस्तावों पर उस स्थिति में विचार किया जाएगा यदि 15.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के अपेक्षित संसाधन ई ई एफ सी निधि/जी डी आर के जरिए जुटाए गए हों। जुटाए गए जी डी आर संसाधनों के 50% तक को विदेश स्थित संयुक्त उद्यम में इक्विटी के रूप में निवेश किया जा सकता है बशर्ते कि उस पर सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त हो। 15.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के पूंजी निवेश के आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए जाएंगे और विशेष समिति की सिफारिश के साथ जांच के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे। प्रत्येक मामले में समग्र लाभ का निर्धारण करने के लिए पैरा 7 में उल्लिखित मानदण्ड के अनुसार उसकी गहन जांच की जाएगी। ई ई एफ सी/जी डी आर संसाधनों के बिना, 15.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के पूंजी निवेशों पर अल्पतः आपवादिक परिस्थितियों में ही विचार किया जाएगा जहां किसी कंपनी के निर्यातों/अन्य आकर्षक लाभों के बहुत अच्छे कार्यकलाप-रिकार्ड हों। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रस्तावों के साथ पैरा 6.1 श्रेणी (ख) के लिए यथा अपेक्षित दस्तावेज होने चाहिए।
- (9) पैरा 11.1 और पैरा 11.2 में क्रमशः "और वाणिज्य मंत्रालय" एवं "वाणिज्य मंत्रालय और" को हटा दिया जाए।

एल एम वास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1997

#### Guidelines for Indian Direct Investment in Joint Ventures and Wholly Owned Subsidiaries Abroad.

**F.No. 4/3/97-EP (OI):—** The following amendments are hereby notified to the Guidelines for Indian Direct Investment in Joint Ventures and Wholly Owned Subsidiaries Abroad, notified vide Notification No. 4/1/93-EP(OI) dated 17-8-95 read with Notification No. 4/1/93-EP(OI) dated 7.11.96 and 26.3.97.

- (1) For Para 1.3, the following para shall be substituted:

"In the light of the above, the following guidelines are issued to elaborate the policy framework in the EXIM Policy. The Reserve Bank of India will accord all necessary approvals, and monitor the progress by prescribing the reporting obligations."

- (2) For Para 2.3, the following para shall be substituted:

"These guidelines do not apply to—

- (i) portfolio investment by Indian parties in foreign concern;
- (ii) direct investment in foreign concerns engaged in the banking sector;
- (iii) overseas direct investments funded out of EEFC balances upto a maximum of US \$ 15 million, permitted by Authorized Dealers; and
- (iv) overseas direct investment funded out of Global Depository Receipts (DGRs) upto a maximum of 50% of GDRs

raised, permitted by Deptt. of Economic Affairs, Min. of Finance.

Cases under Sl. No. (i) to (iv) above shall be considered in terms of separate procedures as prescribed by the Reserve Bank of India/Department of Economic Affairs (Ministry of Finance)."

- (3) In Para 5.1 (iii), after the words "the amount of investment", the following words shall be inserted:

"(net of that amount of EEFC/GDR funding which would have been eligible for clearance under the EEFC/GDR fast track)". Rest of Para 5.1 (iii) remains the same.

- (4) In Para 5.2(3), after the words "Indian JVS/WOSs," the following words shall be added :

"Guarantees shall be taken at 50% of the face value for determining the overall limit of investment."

- (5) In Para 5.7, the words "financial years/financial year" appearing in the third and fourth line of the para, shall be substituted by the words "calendar years/calendar year" respectively.

- (6) For Para 7.1(c), the following para shall be substituted:

"Quantum of the proposed investment and the size of the overseas venture in the context of the resources, net worth and scale of operations of the Indian party including the EEFC/GDR funds proposed as a component of the overseas direct investment; and"

- (7) In Para 7.1(d), after the word "Repatriation", appearing in the first line of the para, the following words shall be inserted:

"(net of that amount of EEFC/GDR funding which would have been eligible for clearance under the EEFC/GDR fast track)". Rest of Para 7.1(d) remains the same.

- (8) For Para 9, the following para shall be substituted:

"Investment proposals in excess of US \$ 15.00 million (not applicable to Indian Rupee investments in Nepal) will be considered if the required resources beyond US \$ 15.00 million are raised through EEFC funds/the GDR route. Upto 50% of GDR resources raised may be invested as equity in overseas joint ventures subject to specific approvals of the Government. Applications for investments beyond US \$ 15.00 million would be received in the R.B.I. and transmitted to Ministry of Finance for examination with the recommendations of the Special Committee. Each case would, with due regard to the criteria outlined in para 7, be subject to rigorous scrutiny to determine its overall benefit. Investments beyond US \$ 15.00 million without EEFC/GDR funding will be considered only in very exceptional circumstances where a company has a strong track record of exports/other compelling benefits. All proposals under this category should be accompanied by the documentation as required for category "B" under para 6.1."

- (9) In Para 11.1 and Para 11.2 the words "and Ministry of Commerce" and "the Ministry of Commerce and" respectively stand deleted.

L. M. VAS Jt. Secy.

